RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 27.12.2017
Page No. 9, Size:(14.87)cms X (15.73)cms.

देश में 81.35 % राशन कार्ड आधार से जुड़े

■ संजय टुटेजा

नई दिल्ली। एसएनबी

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार दूर करने तथा सस्ता अनाज योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाने की कड़ी में देश के विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों के 81.35 प्रतिशत राशन कार्डो को आधार से जोड़ा जा चुका है। राशन कार्डो के सत्यापन की प्रक्रिया में पिछले चार वर्ष अब तक 2.75 करोड़ राशन कार्ड रदद किये जा चुके हैं।

सार्वजनिक वितरण प्राणाली में भ्रष्टाचार हमेशा ही एक बड़ी समस्या रही है। इसी समस्या से निपटने के लिये केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय ने राज्यों की मदद से देश भर में राशन कार्डो को आधार से जोड़ने तथा राशन कार्डो व लाभार्थियों के रिकार्ड का कम्पयूटरीकरण करने की योजना लगभग चार वर्ष पूर्व शुरु की थी। इस योजना के तहत सभी राज्यों में राशन कार्डो के सत्यापन की प्रक्रिया शुरु की गई और राशन कार्डो को आधार से जोड़ा गया। मंत्रालय के अनुसार समूचे रिकार्ड का कम्प्युटरीकरण किये जाने के दौरान वर्ष 2013 से 2017 तक कुल 2.75 करोड़ राशन कार्ड विभिन्न

सत्यापन के दौरान अब तक 2.75 करोड़ राशन कार्ड हुए रद्द

राशन कार्डो व लाभार्थियों के रिकार्ड का हुआ कम्प्युटरीकरण

प्रदेशों व केन्द्र शासित प्रदेशों में रदद किये गये हैं। आधार से जोड़ने के दौरान जाली कार्डो, लाभार्थी की मृत्यु या पलायन, आर्थिक स्थिति में बदलाव आदि कारणों के चलते उक्त राशन कार्डो को रदद किया गया।

मंत्रालय के अनुसार सरकार करीब 17,500 करोड़ रु पये प्रति वर्ष की खाद्य सब्सिडी सस्ते राशन के लिये दे रही है। सब्सिडी की राशि को उचित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिये ही सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण करने के साथ साथ उसमें पारदर्शिता लाने की पहल की है। मंत्रालय के अनुसार विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर शुरु की गई 884 करोड़ रुपये की कम्प्युटरीकरण योजना में केन्द्र भी आर्थिक सहयोग कर रहा है। इस योजना के तहत राशन कार्डो एवं लाभार्थियों के रिकॉर्ड के कंप्यूटरीकरण करने के साथ साथ आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन का कंप्युटरीकरण किया जा रहा है, साथ ही पारदर्शिता पोर्टल और शिकायत निपटान प्रणाली का गठन किया गया है ताकि उपभोक्ताओं की शिकायतों का भी तत्काल समाधान हो।

मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार उचित व्यक्ति तक खाद्यान्न सब्सिडी पहुंचाने के लिये शुरु की गई आधार लिंकिंग योजना के तहत अब तक 81.35 प्रतिशत राशन कार्डो को आधार कार्ड से जोड़ा जा चुका है। उन्होंने बताया कि उचित दर की दुकानों पर होने वाली कुल बिक्री के लेनदेन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखने और प्रमाणीकरण के लिए दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरण को लगाया जा रहा है। अभी तक 23 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में 5.27 लाख उचित दर दुकानों में से 2.83 लाख उचित दर दुकानों पर पर ईपीओएस उपकरण लगाया जा चुका है।